पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 298

- =====
1. सज्जन सिंह, पिता- स्वर्गीय जमुना सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
 2. जय मोहन सिंह, पिता- स्वर्गीय जमुना सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
 3. उमेश सिंह, पिता- स्वर्गीय बच्चा सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
 4. मंजय सिंह, पिता- स्वर्गीय बच्चा सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
 5. सुगी कुँअर, पति- सुरेंद्र सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला- सारण

.....याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. बुन्नी कुँअर, पति- स्वर्गीय रवींद्र सिंह, निवासी- ग्राम- बसंतपुर, प्रोस्ट एवं थाना- पानापुर, जिला-सारण
2. प्रमोद सिंह, पिता- स्वर्गीय रवींद्र सिंह, निवासी- ग्राम- बसंतपुर, प्रोस्ट एवं थाना- पानापुर, जिला-सारण
3. बिनोद सिंह, पिता- स्वर्गीय रवींद्र सिंह, निवासी- ग्राम- बसंतपुर, प्रोस्ट एवं थाना- पानापुर, जिला-सारण

4. प्रभु सिंह, पिता- स्वर्गीय शीतल सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
5. सुभाष सिंह, पिता - स्वर्गीय बच्चा सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
6. अनीता देवी, पिता- स्वर्गीय बच्चा सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
7. पूनम् देवी, पिता- स्वर्गीय बच्चा सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
8. सुमन देवी, पिता- स्वर्गीय बच्चा सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
9. यशोदा देवी, पति- स्वर्गीय बच्चा सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
10. देवेन्द्र सिंह, पिता- स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
11. मुकेश सिंह, पिता- स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
12. रेणु देवी, पति- रिंकू सिंह, पिता- स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण
13. रितु देवी, पति- स्वर्गीय पप्पु सिंह, पिता- स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह, निवासी- ग्राम एवं प्रोस्ट- हरपुर जन, थाना- मशरख, जिला-सारण

.....उत्तरदातागण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री नागेंद्र राय, अधिवक्ता

श्री नवीन निकुंज, अधिवक्ता

श्री कौशलेंद्र राय, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री कुमार उदय सिंह, अधिवक्ता

श्री मदनजीत सिंह, अधिवक्ता

- **भारतीय संविधान - अनुच्छेद 227** - प्रोबेट याचिका में सुधार और परिवर्धन की मांग करने वाली संशोधन याचिका को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज करने को चुनौती - संशोधन याचिका दायर करने में देरी और प्रक्रियात्मक दोषों का आरोप।
- **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश VI नियम 17** - परीक्षण शुरू होने से पहले किसी भी स्तर पर दलीलों में संशोधन जब तक कि देरी को उचित परिश्रम के साथ उचित न ठहराया जाए। (संदर्भित मामले:- बीबी असगरी और अन्य बनाम मोहम्मद कासिम और अन्य (एआईआर 1951 पटना 323) - कुछ वादी का अधिकार दूसरों के ज्ञान के साथ संशोधन शुरू करने के लिए पर्याप्त है - (भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (एआईआर 2022 एससी 4256) - संशोधनों की उदारतापूर्वक अनुमति जब तक कि वे दुर्भावनापूर्ण, समय-बाधित न हों, या मुकदमे की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल न दें।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

दिनांक: 24-06-2024

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रथमतः प्रवेश के बिंदु पर बहस हुई और मैं वर्तमान याचिका को प्रवेश के चरण में ही निपटाने का इरादा रखता हूँ।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ताओं/वादी द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश- I, छपरा द्वारा प्रोबेट केस संख्या 08/2011 में पारित दिनांक 09.10.2018 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है। उक्त मामले में, प्रोबेट याचिका में कुछ संशोधन करने के लिए दिनांक 08.08.2018 को एक संशोधन याचिका दायर की गई है, जिस पर प्रतिवादी प्रथम समूह ने आपत्ति जताई थी, जिन्होंने दावा किया था कि प्रोबेट याचिका सीमा द्वारा वर्जित है। प्रतिवादी प्रथम समूह ने देरी से दाखिल किए जाने के आधार पर संशोधन याचिका पर भी आपत्ति जताई और इस आधार पर भी आपत्ति जताई कि याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'कोड' कहा जाएगा) की धारा 11 के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसी प्रार्थना के साथ एक याचिका पहले भी दायर की गई थी और वापस ले ली गई थी। इसके अलावा, चुनौती इस बिन्दु पर दी गई कि याचिकाकर्ताओं को तथ्य ज्ञात थे फिर भी संशोधन पहले पेश नहीं किया गया तथा संशोधनों के गुण-दोष को भी चुनौती दी गई। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.10.2018 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं की संशोधन याचिका को खारिज कर दिया, जो इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत दृष्टिकोण अपनाया और मामले के गुण-दोष पर विचार किया जो संशोधन याचिका पर निर्णय लेने के चरण में स्वीकार्य नहीं था। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि ट्रायल अभी भी प्रारंभिक चरण में है और संशोधन से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि दो याचिकाकर्ताओं को छोड़कर, अन्य याचिकाकर्ताओं ने संशोधन याचिका पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे और इस आधार पर भी कि संशोधन याचिका दूसरे पक्ष द्वारा आपत्ति में सीमा का मुद्दा उठाए जाने के बाद देरी से दायर की गई थी। हालाँकि, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने **बीबी असगरी एवं अन्य बनाम मो. कासिम एवं अन्य** के मामले में, जिसे **एआईआर (38) 1951 पटना 323** में रिपोर्ट किया गया था, पैराग्राफ संख्या 4 में टिप्पणी की है कि यदि वाद उनके ज्ञान और अधिकार के साथ दायर किया गया था, तो यदि कुछ वादीगण वाद प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र नहीं खोता है। इस प्रकार, यदि कुछ वादी याचिका पर हस्ताक्षर करते हैं और उसे सत्यापित करते हैं तो यह याचिका पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि संशोधन काफी औपचारिक प्रकृति का है। संशोधनों में से एक केवल प्रोबेट याचिका को इतनी देर से लाने के लिए स्पष्टीकरण है, जिसमें मूल वसीयत की प्रमाणित प्रति के खो जाने का उल्लेख है। एक अन्य संशोधन में प्रोबेट याचिका में प्रार्थना वाला भाग जोड़ना शामिल है, क्योंकि वसीयत की प्रोबेट के लिए दायर याचिका में प्रार्थना वाले भाग को अनजाने में छोड़ दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम संजीव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य** के मामले में, जिसे **एआईआर 2022 एससी 4256** के पैराग्राफ संख्या 70 में रिपोर्ट किया गया था में कुछ दिशानिर्देश दिए हैं और माना है कि संशोधनों को उदारतापूर्वक अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक कि यह **द्वेषपूर्ण** न हो या समय समाप्त न हो गया हो या इससे मुकदमे की प्रकृति में परिवर्तन न हो। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रस्तावित संशोधनों

से मुकदमे की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा इन्हें सुनवाई शुरू होने से पहले ही प्रस्तुत किया गया है, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने संशोधन याचिका को खारिज करने में अधिकारिता संबंधी त्रुटि की है तथा विवादित आदेश पारित किया है, जो टिकने योग्य नहीं है।

4. प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जहां तक अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा संशोधन याचिका पर हस्ताक्षर न करने के संबंध में आपत्ति का प्रश्न है, वे याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते तथा इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि यदि एक या दो याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए हों तो यह उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा। हालाँकि, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने पहले 21.05.2018 को उसी संशोधन और उसी प्रार्थना की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जो 08.08.2018 को आदेश के लिए तय की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने बीच में ही इसे वापस ले लिया और इस कारण से दूसरी संशोधन याचिका पर रोक लगा दी गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के मामले में प्रतिवादियों द्वारा अपनी आपत्ति में बताई गई कमी को पूरा करने के लिए संशोधनों को शामिल करने की मांग की गई है और इसी कारण से संशोधन याचिका दायर की गई है और वह भी बहुत देरी के बाद, क्योंकि प्रोबेट याचिका वर्ष 2011 में दायर की गई थी और संशोधन याचिका सात साल बाद दायर की गई है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आक्षेपित आदेश सही एवं विधिक है तथा इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि यदि संशोधन याचिका को अनुमति दी जाती है, तो प्रतिवादियों को प्रोबेट मामले में सीमा के मुद्दे को उठाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

5. तथ्यों और परिस्थितियों तथा पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, यह स्वीकार किया जा सकता है कि संशोधन याचिका साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मामले को तय करने के चरण से पहले दायर की गई है और इसलिए तकनीकी रूप से यह कहा जा सकता है कि सुनवाई शुरू नहीं हुई है और, इसलिए, संशोधन संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान से प्रभावित

नहीं होगा। यदि वादी अपने वादपत्र में कुछ संशोधन करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते संशोधन संहिता के आदेश VI नियम 17 के तहत प्रावधानों को पूरा करता हो, जो इस प्रकार है:

“17. दलीलों में संशोधन- न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार को अपने अभिवचनों को ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों पर परिवर्तित या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है, जो न्यायसंगत हों, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों:

बशर्ते कि विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात संशोधन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि समुचित तत्परता के बावजूद पक्षकार विचारण प्रारम्भ होने से पूर्व मामले को नहीं उठा सकता था।”

6. स्पष्टतः, कार्यवाही के किसी भी चरण में संशोधन लाया जा सकता है, तथा कुछ शर्तों के अधीन परीक्षण शुरू होने के बाद भी, यदि पक्षों के बीच वास्तविक विवाद का निर्धारण करने के लिए इसे आवश्यक समझा जाए। मैं पाता हूँ कि जिन संशोधनों को शामिल करने की मांग की गई है, वे ऐसी प्रकृति के नहीं हैं कि वे मुकदमे की प्रकृति को बदल दें और दूसरे पक्ष के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करें। संशोधनों में से एक केवल व्याख्यात्मक है और तथ्य जो पहले से ही रिकॉर्ड में हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रोबेट याचिका लाने में देरी को स्पष्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें उक्त संशोधनों को लाने में देरी को छोड़कर कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, यदि प्रोबेट याचिका में प्रार्थना वाला भाग गायब है, तो उसे संशोधन के माध्यम से लाने की अनुमति हमेशा दी जा सकती है। इस स्तर पर संशोधन से प्रतिवादियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं होना चाहिए, यदि प्रतिवादियों को उसका खंडन/विरोध करने का अवसर मिले।

7. **बीबी असगरी एवं अन्य** (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के आलोक में, अन्य याचिकाकर्ता द्वारा संशोधन याचिका पर हस्ताक्षर न करना कोई मुद्दा नहीं है। इसके अलावा, इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि संशोधनों से मुकदमे की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है या वे **द्वेषपूर्ण** नहीं लगते हैं या सीमा कानून या किसी अन्य कानून द्वारा वर्जित नहीं हैं और वे पक्षों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्न का निर्धारण करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत होते हैं और **भारतीय जीवन बीमा निगम** (सुप्रा) के मामले में दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद, इन संशोधनों को अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, संशोधनों को प्रोबेट केस दाखिल होने के सात वर्ष बीत जाने के बाद शामिल करने की मांग की गई है, यदि संशोधनों को अनुमति दी जानी है तो प्रतिवादियों को धन के मामले में पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

8. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मामले के चरण और संशोधनों की प्रकृति पर विचार करते हुए, प्रोबेट केस संख्या 08/2011 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश- I, छपरा द्वारा पारित दिनांक 09.10.2018 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष संशोधन के लिए दायर दिनांक 08.08.2018 के आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई की पहली तारीख को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादियों को निर्धारित 10,000/- रुपये की लागत के भुगतान की शर्त पर अनुमति दी जाती है। दूसरे पक्ष को संशोधित लिखित बयान/अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करके याचिकाकर्ताओं/वादी के दावे का खंडन/विरोध करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

9. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकृत की जाती है।

10. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पक्षकारों को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सीमा के मुद्दे सहित सभी मुद्दों को उठाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इस न्यायालय ने किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और जो कुछ भी देखा गया है, वह केवल

वर्तमान याचिका के निपटान के उद्देश्य से हैं और विद्वान विचारण न्यायालय इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से पक्षपातपूर्ण नहीं होगी।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

बालमुकुंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।